भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2869
06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

सांख्यिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु सम्मेलन

2869. श्री हँसमुखभाई सोमाभाई पटेलः
श्री कृपानाथ मल्लाहः
श्री नारायण तातू राणेः
डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सांख्यिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के संदर्भ में राज्य सरकार के मंत्रियों के सम्मेलन के मुख्य उद्देश्य और उपलब्धियाँ क्या हैं;

(ख) सरकार की उप-राज्य स्तर पर सूक्ष्म आकलन करने हेतु विगत सम्मेलन के दौरान चिह्नित की गई विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु क्या योजना है;

(ग) क्या सम्मेलन के दौरान किसी नई पहल का प्रस्ताव रखा गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां.और.कार्य.कार्या.मंत्रा.) ने दिनांक 5 अप्रैल, 2025 को नई दिल्ली में 'सांख्यिकीय प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण' विषय पर राज्य सरकार के मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सामाजिक-आर्थिक संकेतकों के लिए राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर प्रासंगिक, सटीक और सामयिक आंकड़े तैयार करने के महत्व को उजागर करना; राष्ट्रीय और राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए सहयोग/साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों पर जोर देना; साथ ही राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों की सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार के लिए उनकी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं पर विचार-विमर्श करना था।

सम्मेलन के दौरान, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को उप-राज्य (विस्तृत) स्तर पर प्रमुख सांख्यिकीय उत्पादों के सृजन में सहायता हेतु राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के सहयोग से प्रशिक्षण, कार्यशालाएं और सम्मेलन का आयोजन कराने में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के प्रति सुग्राही बनाया गया। इन पहलों, सम्मेलन उनमें से एक है, ने राष्ट्रीय और राज्य सांख्यिकीय प्रणाली के बीच तालमेल बनाकर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकीय क्षमता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ताकि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा अपनाए गए मानकों के अनुरूप विभिन्न संकेतकों के सुसंगत और गुणवत्तापूर्ण डेटा संग्रहण तथा संकलन को सुनिश्चित किया जा सके।

(ख) सर्वेक्षण प्रतिदर्श डिजाइन में मूल स्तर के रूप में 'जिला' को अपनाकर हाल ही में अधिकांश प्रमुख एनएसएस सर्वेक्षणों में जिला-स्तरीय अनुमान तैयार करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है। इसके अलावा, राज्यों द्वारा प्रमुख संकेतकों के वार्षिक जिला स्तरीय अनुमान तैयार करने के लिए एनएसएस सर्वेक्षणों में राज्य की भागीदारी का प्रावधान शुरू किया गया है। इन जिला स्तरीय अनुमानों की परिकल्पना उप-राज्य स्तर पर लक्षित नीति निर्माण को सुविधाजनक बनाने के लिए की जाती है। इसके अतिरिक्त, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय विभिन्न संकेतकों की तैयारी के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गठित समितियों के सदस्य के रूप में कार्य करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करता है।

(ग) और (घ) हाँ महोदय।
सम्मेलन के दौरान, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वार्षिक प्रकाशन नामत: "भारत में महिलाएं और पुरुष 2024: चयनित संकेतक और डेटा" का विमोचन किया तथा इस मंत्रालय की प्रशिक्षण अकादमी, राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (NSSTA) की वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। सूक्ष्म-स्तर/इकाई-स्तर के आंकड़ों के प्रसार में सुधार के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के संशोधित माइक्रो-डेटा पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें वर्तमान में 175 से अधिक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के आंकड़े उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, मार्च 2025 के दौरान आईआईटी गांधीनगर में हाल ही में आयोजित हैकथॉन के दौरान तैयार राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण कोड पर अर्थ संबंधी खोज (सिमेंटिक सर्च) को भी सम्मेलन के दौरान प्रदर्शित किया गया।

*****